

6

सहस्रवर्षीय समायोजन

संख्या / 13-XIX-2 / 38 खाद्य / 2013

1

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 28 जून, 2013

विषय: भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वितरित की जाने वाली चीनी का कय खुले बाजार से किये जाने के सम्बन्ध में राज्य की सहकारी चीनी मिलें एवं कॉरपोरेशन चीनी मिलों से चीनी का कय कर वितरित किये जाने की व्यवस्था एवं सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं को चीनी पर दिये जाने वाले लाभांश ₹ 7.28 प्रति कुन्तल की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से न किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों से भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं० 15(8)/2013-एस०पी०.1 दिनांक 23.04.2013 एवं सं० 19(2)/2013-एस०पी० 17.05.2013 में निर्दिष्ट व्यवस्था के तहत निर्देशों में भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट गुण विनिर्देशों के आलोक में विभिन्न चीनी मिलों से देय लेवी चीनी की व्यवस्था को समाप्त करते हुये पारदर्शी प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि मई, 2013 के पश्चात राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लेवी चीनी वितरित किये जाने की व्यवस्था को प्रभावी रखना चाहती है वे अपने राज्य के उपभोक्ताओं को प्रतिमाह चीनी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान व्यवस्था को प्रभावी रखने के लिये ₹ 18.50 प्रति किलो की दर से सब्सिडी दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप पर सब्सिडी क्लेम का आंकलन कर भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के यहाँ से उपभोक्ताओं हेतु फुटकर लेवी चीनी निर्गमन मूल्य ₹ 13.50 प्रति किलोग्राम वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिये निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान तक सस्ता गल्ला राशन विक्रेता को चीनी के वितरण पर ₹ 7.28 प्रति कुन्तल की दर से लाभांश का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाता था जो वर्तमान जारी नीति के अनुसार समाप्त कर दिया गया है।

उक्त के आलोक में खाद्यायुक्त के पत्र सं० 97/आ०वि०शा०/ले०ची०/2012 दिनांक 31.05.2013 तथा भारत सरकार के उपरोक्त पत्रों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के उपभोक्ताओं के लिये दिनांक 01.03.2000 की जनगणना को आधार मानते हुये 6033 मी०टन (3497 मी०टन गढ़वाल सम्भाग हेतु एवं 2536 मी०टन कुमायूँ संभाग हेतु) प्रति माह कुल वार्षिक 72396 मी०टन

16

1-

तथा 782 मी०टन अर्थात् कुल वार्षिक कोटा 73178 मी०टन चीनी के क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में उक्त निर्धारित वार्षिक कोटे की चीनी के क्रय के लिये राज्य की सहकारी चीनी मिलों से चीनी क्रय किये जाने पर निर्णय की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये माह जुलाई, 2013 से मार्च, 2014 तक कुल 09 माह की चीनी 6033 प्रतिमाह एवं 782 मी०टन वार्षिक त्र्यौहारी कोटे सहित कुल 550790 कुन्टल चीनी क्रय कर वितरण के लिये निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है—

1- भारत सरकार द्वारा निर्धारित चीनी का आवंटन

भारत सरकार के संलग्नक-2 के अनुसार राज्य हेतु चीनी का मासिक कोटा 6033.00 मी०टन तथा वार्षिक त्र्यौहारी कोटा 782 मी०टन निर्धारित किया गया है। वार्षिक त्र्यौहारी कोटे की चीनी का क्रय वर्ष में एक बार ही किया जायेगा।

2- भारत सरकार द्वारा अर्धसैनिक बलों यथा आई०टी०बी०पी०/सी०आई०एस०एफ०/एस०एस०बी०/सी०आर०पी०एफ० के लिये, जिन्हें पूर्व से भारत सरकार द्वारा 100.00 मी०टन चीनी आवंटित की जाती रही है, चीनी आवंटन का उल्लेख नहीं किया गया है। जिसके लिये पृथक से भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा।

अतः राज्य की वार्षिक आवश्यकता 72396 मी०टन चीनी राज्य सरकार द्वारा क्रय किये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित है जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में माह जुलाई, 2013 से माह मार्च, 2014 तक कुल 09 माह की आवश्यकता 6033 मी०टन प्रतिमाह कुल 54297 मी०टन चीनी तथा त्र्यौहारी चीनी वितरण हेतु निर्धारित 782 मी०टन वार्षिक कुल 55079 मी०टन चीनी का क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। चीनी का क्रय राज्य सरकार की सहकारी चीनी मिलों से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय जिससे राज्य में उत्पादित चीनी की खपत राज्य में ही की जा सकेगी तथा परिवहन इत्यादि के व्यय में भी राज्य सरकार को कम व्यय भार वहन करना पड़ेगा।

2- चीनी क्रय का स्रोत

चीनी का क्रय राज्य में स्थापित सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, नादेही सहकारी चीनी मिलें एवं किच्छा एवं डोईवाला कॉरपोरेशन चीनी मिलों से किया जायेगा। चीनी आपूर्ति प्रत्येक सम्भाग के निकटतम चीनी मिल से उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी तथा चीनी मिल से आपूर्ति सुचारु रूप से निर्धारित शर्तों के अनुरूप की जायेगी, जो पृथक से क्रय अनुबन्ध में उल्लिखित होंगी। यदि राज्य में स्थापित चीनी मिलें विभाग को प्रतिमाह चीनी उपलब्ध कराने में असफल रहती हैं तथा स्थानीय बाजार में चीनी की थोक दरें कम प्राप्त होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आती है तो राज्य की आवश्यकता के अनुरूप चीनी का क्रय राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से खुले बाजार से किये जाने का विकल्प खुला रखा जायेगा।

3- चीनी का प्रस्तावित मूल्य

वर्तमान में मिल समिति के पास उत्पादित वर्ष 2012-13 के 1.26 लाख मी०टन चीनी संचित है जिससे मांग के अनुसार चीनी की पूर्ण आपूर्ति निर्वाद रूप से की जा सकती है तथा चीनी की आपूर्ति मिलों द्वारा ₹ 3200.00 प्रति कुन्तल अन्य समस्त करों के अतिरिक्त पर की जायेगी। उपरोक्त दर न्यूनतम होगी, बाजार मूल्य बढ़ने पर बाजार मूल्य के अनुसार बढ़ा हुआ मूल्य लिया जायेगा तथा उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार को उत्पाद शुल्क तथा सैस के रूप

में ₹ 63.86 का भी अतिरिक्त भुगतान किया जाना है। इस प्रकार चीनी का प्रति कुन्टल मूल्य ₹ 3263.86 होगा जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए माह मार्च, 2014 तक मान्य रहेगा। इसके साथ यदि भविष्य में चीनी की दरें बाजार में घटती हैं तो इस पर भी विचार किये जाने का विकल्प खुला रहेगा।

4- पैकिंग की व्यवस्था

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा पूर्व प्राविधानित व्यवस्थानुसार उपभोक्ताओं को निर्वात कड़ाह चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी "भारतीय चीनी मानक ग्रेड (भा0ची0मा0 ग्रेडस)" श्रेणियों में विनिर्दिष्ट एम-29, एस-29, एल-30, एम-30, एस-30, एस-31, एम-31, एस-31 तथा एस.एस. 31 मानकों के अनुरूप तथा 50 किलोग्राम "ए" टिवल नए जूट के बोरो में भर्ती चीनी ही राज्य सरकार को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। जिन चीनी मिलों द्वारा 50 किलोग्राम नये जूट बोरो में चीनी उपलब्ध नहीं करायी जायेगी ऐसी दशा में भारत सरकार के निर्देशानुसार उन चीनी मिलों से प्रति कुन्टल ₹ 13.83 की धनराशि काटकर चीनी का मूल्य भुगतान किया जायेगा।

5- चीनी क्रय के निर्धारित मानक

चीनी का क्रय भारतीय शर्करा मानकों के अनुरूप किया जायेगा। अभी तक राज्य द्वारा "एस- 30" मानक की चीनी आपूर्ति की जाती थी जिसे भविष्य में यथावत् किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को निर्वात कड़ाह चीनी (Vacuum Pan Sugar) कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी भारतीय चीनी मानक ग्रेड श्रेणियों में से ही विनिर्दिष्ट मानकों के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी तथा सहकारी चीनी मिलों द्वारा खाद्य विभाग को भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों एवं नवीनतम फसल वर्ष की ही चीनी उपलब्ध करायी जायेगी।

6- चीनी क्रय हेतु अनुबन्ध की व्यवस्था

क्रय किये जाने वाली चीनी की आपूर्ति सहकारी मिलों से की जायेगी जोकि राज्य सरकार के अधीन है। क्रय व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने से पूर्व दोनों विभागों (खाद्य एवं गन्ना चीनी) के मध्य Terms & Condition शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव जैसी स्थिति हो के मध्य एक अनुबंध पत्र MOU सुचारु रूप से सम्प्रदान सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा, जिस पर भविष्य में विवाद की स्थिति में अन्तिम सुनवाई/निर्णय का अधिकार शासन स्तर पर होगा। अतः तत्काल MOU तैयार कर शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

गन्ना चीनी विभाग द्वारा सूचित प्रति कुन्टल चीनी का मूल्य ₹ 3200 (अतिरिक्त करों सहित) क्रय किये जाने की दिनांक से 31-03-2014 तक मान्य होंगी तथा खाद्य विभाग द्वारा चीनी उठान हेतु मिल परिसर में उपलब्ध कराये गये ट्रकों में चीनी की लोडिंग उपरोक्त वर्णित दरों में सम्मिलित रहेगी।

7- सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं को मिलने वाला लाभांश/परिवहन का भुगतान

राज्य के उपभोक्ताओं के लिये चीनी को वितरित कर रहे उचित दर विक्रेताओं को वर्तमान में ₹ 7.28 प्रति कुन्टल लाभांश तथा गोदाम से उचित दर विक्रेता की दुकान तक परिवहन का भुगतान दिया जा रहा है जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा अभी तक की जा रही थी भविष्य में इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा न किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

8- चीनी के प्रस्तावित क्रय में आने वाला व्यय का आहरण

गन्ना एवं चीनी विभाग द्वारा सूचित मूल्य ₹ 3200.00 प्रति कुन्तल एवं उत्पाद शुल्क तथा सैस के रूप में ₹ 63.86 प्रति कुन्तल की धनराशि में खाद्य विभाग द्वारा चीनी उठान हेतु भेजे गये ट्रकों में चीनी लदान भी सम्मिलित होगी। चीनी लदान हेतु मिल को अतिरिक्त धनराशि खाद्य विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

इस पर होने वाला व्यय भार लेखाशीर्षक "4408 खाद्य भण्डारण एवं भण्डारागारण-01-खाद्य-800 अन्य व्यय- 03-खाण्डसारी शक्कर योजना-31-सामग्री तथा सम्पूर्ति " के नामे डाला जायेगा।

9- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश 51NP/XXVII(5)/13-14 दिनांक 27.06.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।

संख्या 297/13-XIX-2/38 खाद्य/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 5- महालेखकार, उत्तराखण्ड, ओबरोय टॉवर, माजरा, देहरादून।
- 6- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 8- अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 10- सचिव, गन्ना एवं चीनी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र सं0 582(1)XIV-2/2013/08(13)/2013 दिनांक 27.05.2013 के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित।
- 11- आयुक्त, गन्ना एवं चीनी विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 12- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शुगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 13- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 14- वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
- 15- नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड।
- 16- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 17- सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, कुमाँयू सम्भाग/गढ़वाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
- 18- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 19- सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग।
- ✓ 20- एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।